के आधार पर भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया था। बाद में प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 21 करते हुए इसे 13 और जिलों में शुरू किया गया था। प्रायोगिक परियोजनाओं के उत्साहवर्धक परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अब एक अलग केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी तक देश के 99 जिलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 24.28 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुछ और जिलों को शामिल किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश को कवर कर पाना सम्भव नहीं होगा। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना का कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजना की स्थिति पर निर्भर करेगा, यह बता पाना सम्भव नहीं है कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए राशि का आवंटन

2697. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) इस अवधि के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण स्वच्छता हेतु उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि एवं इस संबंध उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यलय के अंतर्गत आबंटित निधिया	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता क्रम के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित खर्च	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित खर्च	निर्मित किए गए शौचालयों की संख्या
1991-92	530.400	1100.00	0.00*	1594.45	98.000	1594.45	88005
1992-93	261.09	1519.00	267.890	1519.00	शून्य	1095.94	69590
1993-94	391.438	801.00	491.438	800.99	659.32	774.99	48335
1994-95	785.000	2784.00	587.25**	200.00	391.00	793.37	36679
							(अक्तूबर, 1994 तक)

*1991-92 के दौरान योजना का अनुमोदन न होने के कारण किसी भी राज्य को केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई थी।

**अभी तक 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है। बकाया केन्द्रीय सहायता यथा समय पर रिलीज की जाएगी।

'Gurudaspur Plan'

2698. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that during disturbances in Punjab, a special project was got prepared by Punjab State Khadi and Village Industries Board to help the rural unemployed youth of Gurudaspur district during 1986 in the name of 'Gurudaspur Plan' ;

(b) whether it is also a fact that on the basis of this plan, an amount of about Rs. 10 crore was sanctioned by the Ministry of Industry to be routed through Khadi and Village Industries Commission;